चीनी के लाइसेंसों की समीक्षा

1866. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चीनी के कारखानों की स्थापना के लिये 1990-91 में जारी किये गये लाइसेंसों की समीक्षा करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री तरुण गोगोई) : इस समय आगे समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न हीं नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश में मत्स्य-पालन उद्योग के विकास के लिये धनराशि

1867. **श्री अजीत जोगी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम ने मध्य प्रदेश को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मत्स्य-पालन उद्योग के समेकित विकास के लिये कितनी धनराशि मंजूर की है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ प्रदान की गई निधियों का पूर्ण उपयोग किया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) मात्स्यिकी उद्योग के एकीकृत विकास के लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा मध्य प्रदेश कोई कोई धनराशि मंजूर नहीं की गयी है ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

कृषि पर आधारित उद्योगों के लिये वित्तीय सहायता

1868. **कुमारी आलिया :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार, कृषि पर आधारित कितने उद्योगों को मंजूरी दी गई और ऐसे कितने उद्योग स्थापित किये गये ;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस प्रयोजनार्थ अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) मुख्यतया इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा गठित बोर्डों और निगमों द्वारा एक सीमित हद तक दी जाने वाली वित्तीय सहायता को छोड़कर केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता देने की कोई योजना नहीं है । पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम,